उत्तराखण्ड सरकार
मा.मुख्यमंत्री प्रेस सूचना ब्यूरो
(सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग)
सचिवालय परिसर, सूभाष रोड, देहरादून
E-mail : infodirector.uk@gmail.com
Website : www.uttarainformation.gov.in

देहरादून 03 दिसम्बर, 2018 (सू.ब्यूरो) प्रेस नोट–03(12/14)

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने जम्मू कश्मीर के पलावाला सेक्टर में अभ्यास सत्र के दौरान शहीद हुए जवान सुरजीत सिंह राणा एवं जवान सूरज सिंह की शहादत पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने दिवंगत आत्मा की शांति एवं दुःख की इस घड़ी में उनके परिजनों को धैर्य प्रदान करने की ईश्वर से कामना की है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा शहीद के परिजनों को हर संभव मदद की जायेगी।

सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग।

देहरादून 03 दिसम्बर, 2018 (सू.ब्यूरो) **प्रेस नोट–02(12/13)**

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने सोमवार को सचिवालय में ''उत्तराखण्ड विजन 2030'' डॉक्यूमेंट का विमोचन किया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने ''उत्तराखण्ड विजन 2030'' का वेब लॉंच भी किया। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि उत्तराखण्ड विजन 2030 में सुनिश्चित किया गया है आज हम कहा खड़े है तथा 2030 तक हमें कहा पहुंचना है। विशेषकर जिस लक्ष्य के साथ भारत सरकार व सयुंक्त राष्ट्र के लक्ष्यों के अनुसार योजनाओं की रूपरेखा रखी गई है जो सतत विकास को सुदृढ़ करे। मुख्यमंत्री ने कहा कि योजनाएं समय पर आरम्भ व समाप्त हो तथा लक्ष्य आधारित हो। विजन 2030 राज्य के भविष्य व आर्थिक विकास की रूपरेखा है।

विजन डॉक्यूमेंट में विशेषकर सतत् विकास लक्ष्यों (एस0डी0जी0) के उपलक्ष्यों को वर्ष 2030 तक पूर्ण कर सतत् विकास हेतु 03 वर्षीय, 07 वर्षीय व 15 वर्षीय दीर्घ कालीन लक्ष्यों को निर्धारित किया जा रहा है। सभी विभागों द्वारा लक्ष्यों की ससमय पूर्ति हेतु रणनीतिक (Strategy) कार्य योजना तैयार की जानी है। राज्य का विजन 2030 डॉक्यूमेंट, 17 सतत विकास लक्ष्य (SDG) के 169 उपलक्ष्यों की समय पर पूर्ति किये जाने के अनुसार तैयार किया गया है। विजन 2030 में राज्य सरकार द्वारा विजन 2030 के विभिन्न पहलुओं का समावेश भी किया गया है। 17 सतत विकास लक्ष्यों को विजन डॉक्यूमेंट में 04 प्रमुख थीम, सतत अजीविका, मानव विकास, पर्यावरण सतत्ता तथा सामाजिक विकास सतत्ता के रूप में परिलक्षित किया गया है। सैक्टरवार कार्य योजनाएं तैयार करने में निश्चित रूप से सुगमता होगी तथा विकास कार्यो का मुख्य–मुख्य सैक्टरवार प्रभावी अनुश्रवण हो सकेगा।

राज्य के आर्थिक विकास हेतु 05 प्रमुख ग्रोथ इंजन चिन्हित किये गये हैं। जीविका कृषि उद्यानीकरण तथा सगंध पादप व जड़ी–बूटी, पर्यटन विकास (साहसिक पर्यटन, ईको टूरिज्म, आध्यात्मिक तथा धार्मिक पर्यटन, High end पर्यटन, ग्रामीण पर्यटन), **आयुष** (योग तथा Wellness केंद्र विकसित करना एवं हैल्थ टूरिज्म को बढ़ावा देना), **हरित ऊर्जा** (स्थानीय स्तर पर छोटे–छोटे बांध अक्षय ऊर्जा), **वानिकी** (वानिकी सेक्टर में Non timber Forest product के प्रभावी व वैज्ञानिक दोहन से स्थानीय आजीविका व्यवस्था को सबल बनाया जाना, जबकि नैसर्गिक पर्यटन के रूप में वन क्षेत्रों के आस–पास के क्षेत्रों को चिन्हित कर रोजगार परक पर्यटन हेतु स्थापित करना एवं ईको सिस्टम सर्विसेज को रेखांकित करना), SDG के लक्ष्यों को निर्धारित अवधि में पूर्ण करने हेतु C2N मॉडल, जिसमें विभागों में आपसी समन्वय (Co-ordination), एक ही प्रवृत्ति की योजनाओं का युक्तिकरण (Rationalization) तथा अभिसरण/संमिलन (Convergence) एवं विभिन्न राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं, शोध संस्थानों, विश्वविद्यालयों, एकेडमिया आदि से वित्तीय एवं तकनीकी सहयोग हेतु नेटवर्किंग कर SDG के महत्वकांक्षी लक्ष्यों को पूर्ण किया जाना है। SDG के लक्ष्यों को पूर्ण करने हेतु आगामी 03 वर्षो, 07 वर्षो तथा 15 वर्षो हेतु प्रस्तावित वित्तीय संसाधनों का प्रक्षेपण (Projection) किया गया है।

सतत विकास लक्ष्यों को निर्धारित समयावधि में प्रभावी रूप से नियोजित, क्रियान्वित तथा अनुश्रवण करने हेतु अपर मुख्य सचिवों, प्रमुख सचिवों तथा सचिव, शिक्षा की अध्यक्षता में गठित कार्य दलों (Working Group) से अपेक्षा की गयी है कि वे शीघ्रातिशीघ्र बैठकें आयोजित कर वर्षिक, त्रैवार्षिक, 7 वर्षीय एवं दूरगामी कार्य योजनायें तैयार कर मॉनिटरिंग फ्रेम वर्क तैयार करेंगे।

SDG हेतु डेटा प्रबंधन व्यवस्था तथा अनुश्रवण एवं मूल्यांकन हेतु अर्थ एवं संख्या निदेशालय एवं नियोजन विभाग का पुनर्गठन तथा सबलीकरण किये जाना आवश्यक है। जिसमें मुख्य रूप से SDG उपलक्ष्यों एवं संकेतकों के गुणवत्तापरक अनुश्रवण तथा मूल्यांकन हेतु तकनीकी का उपयोग कर एकीकृत एम0आई0एस0 प्रणाली एवं जी0आई0एस0 तकनीकी का उपयोग करना आवश्यक होगा।

इस अवसर मुख्य सचिव श्री उत्पल कुमार सिंह, अपर मुख्य सचिव श्री ओम प्रकाश, श्रीमती राधा रतूड़ी सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग।

देहरादून 03 दिसम्बर, 2018 (सू.ब्यूरो) **प्रेस नोट–01(12/12)**

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत के निर्देशानुसार मनरेगा के तहत पिरूल एकत्रीकरण (पर्वतीय क्षेत्रों में चीड़ की सूखी पत्तियां) के कार्य को शामिल करने के लिए भारत सरकार को प्रस्ताव भेजा जाएगा। इसके साथ ही राज्य में मनरेगा के तहत सुगन्धित पौधों के उत्पादन व ऐरॉमेटिक कलस्टर विकसित किए जाएगे। राज्य में पहले से ही ऐरॉमा पार्क विकसित किए जा रहे है। राज्य के लगभग 20,000 कुपोषित बच्चों की माताओं को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार मिशन से जोड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से अपील की कि प्रत्येक अधिकारी सोशल रिस्पॉसिबिलिटी के तहत 2–2 कुपोषित

बच्चों को गोद ले। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कुपोषित बच्चों के परिवारों की भोजन की आदतों, आर्थिक, सामाजिक पृष्ठभूमि का विस्तृत अध्ययन किया जाए।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने सोमवार को सचिवालय में उत्तराखण्ड राज्य रोजगार गांरटी परिषद (मनेरगा) के कार्यो की समीक्षा के दौरान सभी जनपदों के मुख्य विकास अधिकारियों को निर्देश दिए की मनेरगा के तहत वर्मी कपोस्ट के साथ ही शिवांश खाद के निर्माण को प्रोत्साहित किया जाए। शिवांश खाद निर्माण व उपयोग राज्य के 15 चिहिन्त ऑगेनिक ब्लॉकों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया जाएगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार हरिद्वार कर्तारपुर गांव में देशी गाय के संरक्षण व संवर्धन के साथ यहां के दूध की मार्केटिंग व आपूर्ति दिल्ली तक की जाएगी। अल्मोड़ा में कोसी नदी के पुनर्जीवीकरण के सफल मॉडल को प्रत्येक जिले में अपनाया जाएगा। प्रत्येक जिले में कोसी मॉडल के आधार पर दो से तीन नदियों को पुनर्जीवीकृत किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि गौशालाओं या पशु गृहों को भी सुविधाजनक व आरामदायक बनाए जाने पर कार्य किया जाय ताकि पशुओं के जीवन स्तर में गुणात्मक सुधार हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड की वन पंचायतें सुगन्धित पौधों व अन्य जड़ी बूटियों के उत्पादन के साथ ही किस प्रकार अन्य व्यावसायिक गतिविधियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है, इस कार्ययोजना पर कार्य करने की जरूरत है। मनरेगा के तहत पिथौरागढ़, उत्तरकाशी व रूद्रप्रयाग में मत्स्य पालन में ट्राउट मछली पालन पर विशेष फोकस किया जाए। मनरेगा के तहत ही उद्यान विभाग द्वारा अखरोट के क्लस्टर विकसित करने पर फोकस किया जाए। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि राज्य में ग्रामीण हाट कल्चर तेजी से विकसित हो रहा है। ग्रामीण हाट बनाने के लिए भूमि की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए व नए ग्रामीण हाट बनाए जाएं।

मुख्यमंत्री ने बैठक में उपस्थित ग्राम प्रधान व अन्य जन प्रतिनिधियों की मनरेगा के तहत समय पर भुगतान न होने की शिकायतों को गम्भीरता से लेते हुए प्रमुख सचिव ग्राम्य विकास को प्रकरण की जांच के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने मनरेगा के कार्यो की सोशल ऑडिट को और अधिक पारदर्शी व सृदृढ करने के निर्देश दिए। उन्होने मनरेगा के तहत भूमि उत्पादकता में सुधार, मत्स्य पालन, बंजर भूमि के विकास, पशुबाड़ा निर्माण, उद्यानीकरण, रेशम, वनीकरण के माध्यम से आजीविका में सुधार पर विशेष फोकस करने के निर्देश दिए।

बैठक के दौरान जानकारी दी गई कि भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा उत्तराखण्ड को मनरेगा में उत्कृष्ट कार्य करने हेतु पांच पुरस्कार मिले है। मनरेगा के कार्यो में पारदर्शिता के उददेश्य से कार्य प्रारम्भ से पूर्व (कार्यस्थल), कार्य के दौरान एवं कार्य समाप्ति पर जियोटेगिंग की जा रही है। इसके साथ ही बैठक में मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने महात्मा गांधी नरेगा के तहत बनाए जाने वाले आंगणनों में एकरूपता व त्रुटिहीनता सुनिश्चित करने हेतु सिक्योर सॉफ्टवेयर का शुभारम्भ किया। सिक्योर सॉफ्टवेयर का प्रयोग जनपद देहरादून से प्रारम्भ किया गया है। 15 जनवरी 2019 तक इसे सभी जनपदों में लागू कर दिया जाएगा।

बैठक में अपर मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी, प्रमुख सचिव श्रीमती मनीषा पंवार, सभी जिलों के मुख्य विकास अधिकारी व अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग।